सिलिकोसिस और श्रमिकों का अधिकार

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा (सामान्य अध्ययन-II एवं III) | समाचार संदर्भ:मई 2026 में गुजरात उच्च न्यायालय के अप्रैल आदेश पर सामने आई चर्चा। | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

मई 2026 में सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों तक कल्याणकारी लाभ पहुंचाने का प्रश्न चर्चा में आया। गुजरात उच्च न्यायालय के 28 अप्रैल 2026 के आदेश में राज्य की उपलब्ध योजनाओं और नामित नोडल अधिकारियों की जानकारी अधिसूचित करने तथा उसका पर्याप्त प्रचार करने की आवश्यकता बताई गई थी। मामला केवल सहायता की घोषणा का नहीं, उसे प्राप्त करने के रास्ते का भी था। आदेश में दर्ज चिंता यह थी कि अलग-अलग योजनाओं के लिए प्रभावित व्यक्ति को अलग अधिकारियों और अधिकार-क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है। गंभीर रोग, रोजगार खोने और आय घटने की स्थिति में यह प्रक्रिया स्वयं एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए सिलिकोसिस का प्रश्न चिकित्सा, कार्यस्थल सुरक्षा और प्रशासनिक पहुंच, तीनों से जुड़ा है। **पहले समझें: सिलिकोसिस क्या है?** सिलिकोसिस फेफड़ों का ऐसा व्यावसायिक रोग है जो श्वसन योग्य क्रिस्टलीय सिलिका के सूक्ष्म कण सांस के साथ भीतर जाने से होता है। ये कण फेफड़ों के ऊतकों में नुकसान और स्थायी निशान पैदा कर सकते हैं। रोग में हो चुकी क्षति को पूरी तरह उलट देना संभव नहीं माना जाता, लेकिन हानिकारक धूल-संपर्क रोककर इसकी रोकथाम की जा सकती है।

हर धूल एक जैसी नहीं:

सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। पत्थर, रेत, कंक्रीट और कुछ कृत्रिम पत्थर उत्पादों में इसकी क्रिस्टलीय अवस्था मौजूद हो सकती है। काटने, घिसने, ड्रिल करने और पॉलिश करने से हवा में इतने छोटे कण जा सकते हैं कि वे फेफड़ों के भीतर तक पहुंचें। खतरा केवल धूल दिखने या न दिखने से तय नहीं होता। इसलिए सिलिकोसिस को हर प्रकार के सामान्य वायु प्रदूषण का दूसरा नाम नहीं मानना चाहिए। पदार्थ की प्रकृति, कणों का आकार, संपर्क की तीव्रता और अवधि महत्वपूर्ण हैं। खनन और पत्थर तोड़ने के साथ निर्माण, सुरंग, सैंडब्लास्टिंग तथा पत्थर के काउंटर बनाने जैसे कामों में भी जोखिम हो सकता है। एक उपयोगी अंतर यह भी है कि रोग का स्रोत और उसका सामाजिक परिणाम अलग स्तरों पर दिखते हैं। स्रोत कार्यस्थल की धूल हो सकता है, लेकिन परिवार पर इलाज का खर्च, कमाई का नुकसान और देखभाल का बोझ आता है। इसी कारण रोकथाम को केवल व्यक्ति की सावधानी तक सीमित नहीं किया जा सकता।

गुजरात आदेश का वास्तविक आशय:

28 अप्रैल के आदेश में राज्य की ओर से बताया गया कि 21 अप्रैल 2026 के परिपत्र के अनुसार संबंधित तालुका के सहायक सरकारी श्रम अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन भरने और जमा करने में सहायता तथा लागू राज्य योजनाओं के लाभ के वितरण में प्रशासनिक स्पष्टता था। न्यायालय ने उपलब्ध योजनाओं की सूची और नोडल अधिकारी का विवरण अधिसूचित करने को कहा। साथ ही प्रभावित लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रचार की जरूरत बताई। यहां मुख्य सीख यह है कि लाभ का कागज पर होना और लाभार्थी को उसका रास्ता पता होना अलग बातें हैं। आदेश को किसी एक नई सर्वदेशीय सिलिकोसिस पेंशन की घोषणा मानना गलत होगा। उसमें विभिन्न लागू राज्य योजनाओं और उनसे लाभ पाने की प्रक्रिया का प्रश्न था। किसे कौन-सा लाभ मिलेगा, यह संबंधित योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा। इस लेख से किसी व्यक्ति की पात्रता या निश्चित भुगतान का निर्णय नहीं निकलता। आदेश में आगे की सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख रखी गई थी। वह उस समय की प्रक्रिया का विवरण है, आज भी अनुपालन अधूरा होने का प्रमाण नहीं। यहां मूल आदेश से प्रशासन की सीख ली गई है; बाद की हर सुनवाई या प्रत्येक लाभ के वास्तविक वितरण का अंतिम लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

रोकथाम, मुआवजा और पुनर्वास:

रोकथाम का उद्देश्य बीमारी होने से पहले जोखिम घटाना है। मुआवजा हुई क्षति के लिए राहत है। पुनर्वास प्रभावित व्यक्ति और परिवार को जीवन तथा आजीविका फिर व्यवस्थित करने में सहायता देता है। इनमें से किसी एक को दूसरे का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। यदि केवल बीमारी के बाद भुगतान पर ध्यान रहे और धूल पैदा करने वाली प्रक्रिया न बदले, तो नए श्रमिक भी बीमार होते रहेंगे। दूसरी ओर, भविष्य की बेहतर सुरक्षा के नाम पर पहले से प्रभावित लोगों को राहत से वंचित करना भी अनुचित है। नीति को वर्तमान पीड़ित और भविष्य के जोखिम, दोनों देखने चाहिए। अगस्त 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भी दो मुख्य पहलू अलग किए थे। उद्योगों के पर्यावरणीय मानकों और रोकथाम संबंधी निगरानी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका तथा प्रभावित श्रमिकों या परिजनों को मुआवजा मिलने की निगरानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बताई गई थी। संबंधित संस्थाओं और राज्य अधिकारियों के सहयोग पर जोर था। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि किसी भी श्रमिक को बिना जांच एक समान रकम स्वतः मिलेगी। निर्णय में पुराने मामलों, पूर्व निर्देशों और विशिष्ट परिस्थितियों का संदर्भ है। पुराने भुगतान के आंकड़े उठाकर वर्तमान भारत के हर व्यक्ति के लिए सार्वभौमिक दर घोषित करना भ्रामक होगा।

सुरक्षा की प्राथमिकता क्या हो?

केवल मास्क बांट देना पर्याप्त कार्यस्थल नीति नहीं है। नियंत्रण का बेहतर क्रम खतरे को खत्म करने अथवा कम जोखिम वाली सामग्री अपनाने से शुरू होता है, जहां सुरक्षित विकल्प संभव हो। उसके बाद प्रक्रिया और उपकरण के स्तर पर धूल कम करने के उपाय आते हैं। प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अतिरिक्त परतें हैं। पत्थर काटते समय उपयुक्त गीली विधि, स्थानीय धूल-निकासी, प्रक्रिया को अलग घेरना और सही फिल्टर वाली सफाई व्यवस्था उपयोगी उपाय हो सकते हैं। इन्हें प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा काम और सामग्री के अनुसार तय करना चाहिए। कोई एक उपकरण हर कार्यस्थल के लिए पर्याप्त नहीं होता। सूखी झाड़ू और दबाव वाली हवा से सफाई धूल को दोबारा हवा में उड़ा सकती है। इसलिए सफाई भी सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। मशीन लगने के बाद उसका रखरखाव, पानी और फिल्टर की उपलब्धता तथा नियंत्रण वास्तव में काम कर रहा है या नहीं, यह जांचना जरूरी है। श्वसन सुरक्षा उपकरण की जरूरत हो तो उसका चयन, सही फिट और उपयोग संबंधी प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं। फिर भी पूरे खतरे का बोझ श्रमिक के चेहरे पर पहने उपकरण पर डाल देना उचित नहीं। स्रोत पर नियंत्रण और सुरक्षित उत्पादन व्यवस्था नियोक्ता तथा निरीक्षण तंत्र की जिम्मेदारियों से अलग नहीं हैं।

रोग की पहचान क्यों कठिन है?

असंगठित और प्रवासी श्रमिक कई स्थानों पर काम करते हैं। कार्यस्थल का रिकॉर्ड, संपर्क की अवधि और बीमारी की पहचान अलग संस्थाओं में बिखरे हो सकते हैं। यदि मजदूर के पास नियुक्ति पत्र ही न हो, तो केवल दस्तावेजों पर निर्भर व्यवस्था वास्तविक पीड़ित को बाहर कर सकती है। इस समस्या का उत्तर बिना चिकित्सकीय जांच हर खांसी को सिलिकोसिस मान लेना नहीं है। उत्तर है सुलभ चिकित्सा, कार्य-इतिहास दर्ज करना, उचित जांच और सहायता प्राप्त आवेदन प्रक्रिया। बीमारी का निदान विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा का विषय है; यह लेख स्वयं निदान या उपचार का विकल्प नहीं। प्रवासी श्रमिक के लिए राज्यों के बीच समन्वय भी महत्वपूर्ण है। काम एक राज्य में हुआ हो और परिवार दूसरे में रहता हो, तो सूचना और लाभ की प्रक्रिया में संपर्क टूट सकता है। एक स्पष्ट संपर्क अधिकारी और स्थिति जानने का सरल रास्ता इस दूरी को कम कर सकता है।

नीति को परिणाम से कैसे जांचें?

सुरक्षित कार्यस्थल: केवल निरीक्षण की संख्या नहीं, जोखिम वाले कामों में धूल-संपर्क कितना घटा, यह देखा जाए। उल्लंघन की पहचान के बाद सुधार और उसकी पुष्टि भी जरूरी है। **सुलभ सहायता:** आवेदन कहां करना है, कौन मदद करेगा और कौन-से दस्तावेज चाहिए, यह सरल भाषा में मिले। जरूरतमंद व्यक्ति को विभागों के बीच बार-बार न भेजा जाए। **वास्तविक वितरण:** योजना स्वीकृत होने, राशि मंजूर होने और परिवार तक रकम पहुंचने को अलग दर्ज किया जाए। केवल बजट घोषणा को भुगतान का प्रमाण न माना जाए। **सम्मानजनक पुनर्वास:** रोजगार की क्षमता, परिवार की परिस्थिति और इलाज की जरूरत के अनुसार सहायता हो। गंभीर रोग के बाद श्रमिक को फिर उसी धूल-भरे काम में लौटने को मजबूर न होना पड़े।

निष्कर्ष:

सिलिकोसिस रोके जा सकने वाले जोखिम के सामने कमजोर श्रमिक की स्थिति उजागर करता है। समाधान बीमारी के बाद की राहत तक सीमित नहीं हो सकता। सुरक्षित उत्पादन, समय पर पहचान, सरल आवेदन और वास्तविक पुनर्वास को जोड़ना होगा। किसी योजना की सफलता उसकी अधिसूचना से आगे, प्रभावित व्यक्ति के जीवन में आए सुधार से मापी जानी चाहिए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास:

प्रश्न: 'सिलिकोसिस का प्रभावी समाधान कार्यस्थल की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक वास्तविक पहुंच, दोनों मांगता है।' चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

▼ उत्तर की रूपरेखा देखें

परिचय:रोग के रोकथाम योग्य व्यावसायिक कारण बताएं। **मुख्य भाग:**धूल-नियंत्रण का क्रम, असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की बाधाएं, निदान, सहायता प्राप्त आवेदन, मुआवजा और पुनर्वास पर विचार करें। **निष्कर्ष:**घोषणा के बजाय सुरक्षित काम और वास्तविक लाभ को सफलता की कसौटी बनाएं।

स्रोत और सीमाएँ

- गुजरात उच्च न्यायालय का 28 अप्रैल 2026 का मूल आदेश
- मई 2026: योजनाओं और नोडल अधिकारी पर रिपोर्ट
- सर्वोच्च न्यायालय का 6 अगस्त 2024 का निर्णय
- सिलिका और श्रमिक स्वास्थ्य
- धूल-नियंत्रण और सुरक्षित कार्य पद्धतियां
- गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण: संबंधित सरकारी प्रस्ताव और परिपत्र
- **सीमाएँ:** 28 अप्रैल 2026 का आदेश नई सर्वदेशीय योजना या एक समान मुआवजे की घोषणा नहीं है; किसी की पात्रता या निश्चित राशि इस लेख से नहीं निकलती। जुलाई की सुनवाई-तारीख उस समय की प्रक्रिया थी, वर्तमान अनुपालन-स्थिति का दावा नहीं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का परिपत्र-पैकेट आंशिक रूप से ही पढ़ा जा सका; उसे वर्तमान अधिसूचना-पालन का प्रमाण नहीं माना गया। रोग का निदान विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा का विषय है; यह लेख चिकित्सा या आवेदन-मार्गदर्शन नहीं है।

इसी विषय का प्रारंभिक परीक्षा (तथ्य) लेख: सिलिकोसिस और श्रमिकों का अधिकार — प्रमुख तथ्य